Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

जन्नत बानो कायमखानी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * जन्नत बानो कायमखानी

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24416387

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक, सामाजिक एवं चुनावी दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका संबंध विधायी संस्थाओं में उपस्थिति, राजनीतिक निर्णय-निर्माण में सहभागिता तथा समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति से भी होता है। राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया गया है। इस अध्ययन में राजस्थान के मुस्लिम समुदाय की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ विधानसभा चुनावों में उसकी राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी विभिन्न चुनावों और विधानसभाओं में अलग-अलग स्वरूप में दिखाई देती है। प्रतिनिधित्व के विश्लेषण में केवल निर्वाचित विधायकों की संख्या ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया, समुदाय के भीतर सामाजिक एवं लैंगिक विविधता तथा विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधियों की सक्रियता भी महत्त्वपूर्ण है। अतः राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक समावेशन, राजनीतिक समानता और सामाजिक न्याय के व्यापक प्रश्नों से जुड़ा हुआ है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 11-09-2026
- **Accepted:** 18-11-2026
- **Published:** 21-11-2026
- **MRR:**4(11); 2026: 256-259
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

कायमखानी ज बा. राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(11): 256-259.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मूल शब्द: मुस्लिम अल्पसंख्यक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजस्थान विधानसभा, चुनावी राजनीति, लोकतांत्रिक समावेशन, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक न्याय।

© 2026 जन्नत बानो कायमखानी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

प्रस्तावना

लोकतंत्र शासन की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें जनता की सहभागिता, समानता, स्वतंत्रता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को विशेष महत्त्व प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता केवल नियमित चुनावों के आयोजन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों और समूहों को राजनीतिक संस्थाओं में कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से नागरिकों की समस्याएँ, आवश्यकताएँ और अपेक्षाएँ शासन तथा नीति-निर्माण की प्रक्रिया तक पहुँचती हैं। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक समुदायों की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक समावेशन के महत्त्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं।1

भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषायी तथा बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और सामाजिक समूहों के लोग निवास करते हैं। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता तथा धार्मिक अधिकार प्रदान किए हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध तथा अनुच्छेद 25 से 30 धार्मिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य देश की विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना में सभी समुदायों को समान अधिकार और अवसर उपलब्ध कराना है।2

भारतीय समाज में मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। इसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन भारतीय लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अधिकारों तथा समान प्रतिनिधित्व के प्रश्न को समझने के लिए आवश्यक है। मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन केवल उसकी जनसंख्या अथवा मतदान व्यवहार के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए विधायिकाओं में उसकी उपस्थिति, राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों का चयन, चुनावों में सफलता तथा शासन और नीति-निर्माण में सहभागिता का अध्ययन भी आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा गठित सच्चर समिति ने वर्ष 2006 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी स्थिति से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए।3

राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी भी समुदाय की लोकतांत्रिक भागीदारी का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। विधानसभा में किसी समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति से उस समुदाय के मुद्दों को विधायी मंच पर उठाने का अवसर प्राप्त होता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है, क्योंकि चुनावों में उम्मीदवारों का चयन और उन्हें टिकट प्रदान करना राजनीतिक प्रतिनिधित्व की संभावनाओं को प्रभावित करता है। राजस्थान की चुनावी राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रमुख प्रतिस्पर्धा रही है। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में मुस्लिम उम्मीदवारों को मिलने वाले चुनावी अवसर, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी भागीदारी तथा उनकी चुनावी सफलता का अध्ययन राज्य की राजनीतिक संरचना को समझने में सहायक है।4

राजस्थान मे लोकसभा एवं विधान सभा मे मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति-

राजस्थान में लोकसभा एवं विधानसभा स्तर पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को यदि 1952 से 1999 की अवधि में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि यह समस्या "राजनीतिक सहभागिता की कमी" से अधिक "संरचनात्मक राजनीतिक की कमी को दर्शाता है। स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव (1952) से ही राजस्थान का राजनीतिक ढाँचा उच्च जातीय-क्षेत्रीय वर्चस्व, राजपूत-ब्राह्मण प्रभुत्व और कांग्रेस-केंद्रित प्रतिस्पर्धा द्वारा नियंत्रित रहा, जिसमें मुस्लिम समुदाय की भूमिका मुख्यत: सीमित रही| राजस्थान की विधानसभा मे मुस्लिम प्रतिनिधित्व की गणना की जाए तो आँकड़े मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम नजर आते हैं और राजस्थान की राजनीति में मुस्लिमों की ऐसी पिछड़ी स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही है| स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक 78 वर्षों के लंबे शासनकाल में राजस्थान में केवल एक मुस्लिम मुख्यमंत्री रहें हैं,बरकतुलह खान(1971-1973 तक) वह भीं बहुत कम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के पद पर रहे और अब तक के लोकसभा चुनावों के परिणामों को देखा जाए तो मात्र 10वीं मे झुंझुनू से मो. अय्यूब खान सांसद बने साथ ही प्रथम विधानसभा से लेकर पंद्रवी विधानसभा में भी मुस्लिम विधायक बहुत कम चुने गए हैं|5 जिनका निम्नलिखित सारणी द्वारा विश्लेषण किया गया है-

प्रथम विधानसभा(1952) से लेकर अब तक (16वीं) कि विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व

सारणी- 1

क्र.सं.	विधान सभा	वि.स. सदस्य संख्या	मुस्लिम विधायक	प्रतिशत
1	पहली	160	2	1.42%
2	दूसरी	176	4	2.27%
3	तीसरी	176	3	1.70%
4	चौथी	184	5	2.71%
5	पाँचवी	184	6	3.26%
6	छठी	200	9	4.5%
7	सातवीं	"	10	5%
8	आठवीं	"	8	4%
9	नौवीं	"	8	4%
10	दसवीं	"	5	2.5%
11	ग्यारहवीं	"	13	6.5%

© 2026 जन्नत बानो कायमखानी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

12	बाहरवीं	"	5	2.5%
13	तेरहवीं	"	12	6%
14	चौदहवीं	"	2	1%
15	पंद्रहवीं	"	9	4.5%
16	सोहलवीं	"	5	2.5%
योग	16	-	106	-

स्त्रोत-Election Commission of India-State Election, to the Legislative Assembly of Rajasthan

सारणी के अनुसार राजस्थान विधानसभा की प्रथम विधानसभा में कुल 160 सदस्यों में केवल 2 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए थे, जो कुल सदस्य संख्या का लगभग 1.25 प्रतिशत था। इसके बाद दूसरी विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। तीसरी विधानसभा में यह संख्या घटकर 3 रह गई, जबकि चौथी और पाँचवीं विधानसभा में क्रमशः 5 और 6 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए।

छठी विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई, जो पूर्ववर्ती विधानसभाओं की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि थी। सातवीं विधानसभा में यह संख्या 10 तक पहुँच गई। आठवीं एवं नौवीं विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 8-8 रही। दसवीं विधानसभा में यह संख्या घटकर 5 हो गई, जबकि ग्यारहवीं विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और मुस्लिम विधायकों की संख्या 13 तक पहुँच गई। यह प्रस्तुत आँकड़ों में सर्वाधिक संख्या है। इसके पश्चात बारहवीं विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर 5 रह गई। तेरहवीं विधानसभा में यह संख्या पुनः बढ़कर 12 हो गई। इसके विपरीत चौदहवीं विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर मात्र 2 रह गई, जो प्रस्तुत आँकड़ों में सबसे कम संख्या है। पंद्रहवीं विधानसभा में यह संख्या बढ़कर 9 हो गई, जबकि सोलहवीं विधानसभा में पुनः घटकर 5 रह गई।7

राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति

सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि राजस्थान विधानसभा में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व सदैव सीमित रहा है। सोलह विधानसभाओं के उपलब्ध आँकड़ों में किसी भी विधानसभा में मुस्लिम विधायकों का प्रतिशत 7 प्रतिशत तक नहीं पहुँचा। ग्यारहवीं विधानसभा में प्रतिनिधित्व 6.5 प्रतिशत तक पहुँचना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन इसके बाद बारहवीं विधानसभा में यह घटकर 2.5 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार तेरहवीं विधानसभा में 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, लेकिन चौदहवीं विधानसभा में यह घटकर केवल 1 प्रतिशत रह गया। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि राजस्थान की चुनावी राजनीति में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व निरंतर एवं स्थिर नहीं रहा है।

राजस्थान में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का स्वरूप

राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समझने के लिए आवश्यक है। राज्य में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक संरचना, जनसांख्यिकीय स्थिति, क्षेत्रीय वितरण, शिक्षा, व्यवसाय तथा आर्थिक परिस्थितियों में विविधता पाई जाती है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और टोंक जैसे शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग शिक्षा, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जबकि पश्चिमी

राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और जालौर जैसे क्षेत्रों में अनेक परिवार पारंपरिक व्यवसायों, पशुपालन, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों पर निर्भर हैं। समुदाय के भीतर उपजातीय विविधता और ग्रामीण-शहरी सामाजिक अंतर भी इसकी सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार राजस्थान का मुस्लिम समुदाय एकरूप न होकर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमियों वाला समुदाय है।6

शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से शोध-प्रबंध में मुस्लिम समुदाय की कुछ चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। इसमें उच्च शिक्षा में सीमित भागीदारी, स्थायी रोजगार के अवसरों की कमी तथा स्वरोजगार और असंगठित क्षेत्र पर निर्भरता का उल्लेख है। शोध-प्रबंध में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, समुदाय की औसत वार्षिक आय राज्य के औसत से कम बताई गई है तथा ग्रामीण मुस्लिम परिवारों की आर्थिक स्थिति शहरी परिवारों की तुलना में अधिक कमजोर दर्शाई गई है। इसी प्रकार कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में समुदाय की भागीदारी का भी विश्लेषण किया गया है। इन परिस्थितियों का प्रभाव राजनीतिक जागरूकता, चुनावी भागीदारी और नेतृत्व के अवसरों पर पड़ सकता है। अतः सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के व्यापक संदर्भ में समझना आवश्यक है।7

प्रमुख निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आता है कि राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष रहा है। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न विधानसभा चुनावों में मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी निरंतर बनी रही है, किंतु विधानसभा में उसकी वास्तविक उपस्थिति में समय-समय पर उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐतिहासिक चुनावी आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कभी मुस्लिम विधायकों की संख्या में वृद्धि हुई, तो कभी इसमें उल्लेखनीय कमी आई। उदाहरण के लिए, वर्ष 1972 में छह, 1977 में नौ तथा 1998 में तेरह मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए, जबकि 2003 में यह संख्या घटकर पाँच रह गई। वर्ष 2008 में पुनः बारह मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए। यह स्थिति दर्शाती है कि राजस्थान में मुस्लिम समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी निश्चित प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं रहा, बल्कि यह चुनावी परिस्थितियों, राजनीतिक दलों की नीतियों और सामाजिक संरचना से प्रभावित होता रहा है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि राजस्थान में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है। समुदाय के भीतर

© 2026 जन्नत बानो कायमखानी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

शैक्षणिक स्तर, रोजगार, आय, पारंपरिक व्यवसाय और ग्रामीण-शहरी परिस्थितियों में विविधता पाई जाती है। समुदाय का एक बड़ा हिस्सा व्यापार, हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग, पशुपालन तथा असंगठित क्षेत्र के विभिन्न व्यवसायों से जुड़ा हुआ है। शिक्षा और आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुँच, स्थायी रोजगार के अवसरों की कमी तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ राजनीतिक नेतृत्व के विकास और सार्वजनिक संस्थाओं में भागीदारी को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन उसकी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से अलग करके नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि राजनीतिक दलों को मुस्लिम समुदाय सहित सभी अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधित्व को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उम्मीदवारों के चयन में केवल चुनावी समीकरणों को आधार न बनाकर उनकी योग्यता, सामाजिक कार्यों, जनाधार और राजनीतिक अनुभव को भी महत्त्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के युवाओं को स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और विधानसभा चुनावों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे राजनीतिक नेतृत्व का आधार व्यापक होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं में समुदाय की सहभागिता बढ़ सकेगी।

निष्कर्ष

राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सामाजिक विविधता और राजनीतिक समावेशन से जुड़ा एक व्यापक विषय है। प्रस्तुत अध्ययन में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं जनसांख्यिकीय स्थिति के साथ-साथ विधानसभा चुनावों में उसकी राजनीतिक भागीदारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, राजनीतिक दलों की भूमिका और विधायी गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद से राजस्थान की विधानसभा में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति बनी रही है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व विभिन्न चुनावों में असमान और परिवर्तनशील रहा है। यह स्थिति राजनीतिक दलों की प्रत्याशी चयन नीति, निर्वाचन क्षेत्रों की सामाजिक संरचना, चुनावी प्रतिस्पर्धा तथा समुदाय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई है।

समग्र अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि किसी समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल उसकी जनसंख्या अथवा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से निर्धारित नहीं होता। वास्तविक प्रतिनिधित्व का संबंध इस बात से भी है कि उस समुदाय के प्रतिनिधि शासन और नीति-निर्माण की प्रक्रिया में कितनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम विधायकों द्वारा विधानसभा में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, विकास और जनहित से संबंधित विषयों को उठाना उनके प्रतिनिधित्व के गुणात्मक पक्ष को दर्शाता है। इसी प्रकार विधानसभा की समितियों, विधायी चर्चाओं और निर्णय-प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सार्थकता का महत्त्वपूर्ण आधार है।

संदर्भ सूची

1. Pitkin HF. प्रतिनिधित्व की अवधारणा. बर्कले: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस; 1967.
2. भारत सरकार. भारत का संविधान. अनुच्छेद 14, 15 एवं 25–30. नई दिल्ली: भारत सरकार।
3. Hasan Z. समावेशन की राजनीति: जाति, अल्पसंख्यक एवं सकारात्मक कार्रवाई. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2018.
4. भारत सरकार. भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति: एक रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2006.
5. Adeney K, Swenden W. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता-साझेदारी: भारत में अनौपचारिक सहमति-आधारित व्यवस्था (और उसका पतन?). स्विस पॉलिटिकल साइंस रिव्यू; 2019.
6. Sharma BD. राजस्थान में सामाजिक स्तरीकरण एवं राजनीतिक शक्ति।
7. नीति आयोग. भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से वंचित समुदायों के सशक्तिकरण हेतु नीतिगत रूपरेखा. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2015. पृ. 84.
8. भारत निर्वाचन आयोग. राजस्थान विधानसभा के लिए राज्य विधानसभा निर्वाचन. नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग।
9. सच्चर R. भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति: प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2006.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Author

जन्नत बानो कायमखानी राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) में शोधार्थी हैं। उनकी अकादमिक रुचि राजनीति विज्ञान, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक अधिकारों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं समावेशी लोकतंत्र के अध्ययन में है।

© 2026 जन्नत बानो कायमखानी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/